Title: Need to set up another Commission to probe 1984 anti-sikh riots.

श्री ज़ोरा सिंह मान (फिरोजपुर): गृह मंत्री साहब ने दूसरे सदन में यह घोषणा की थी कि सरकार सभी राजनैतिक दलों की सहमति से १९८४ के सिख विरोधी कत्लेआम की जांच के लिए एक और कमीशन गठित करने को तैयार है। इसमें आम सहमति की बात इसलिए कही गई क्योंकि शायद सरकार यह नहीं चाहती कि उस पर अपने राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की हमेशा से यह विचारधारा रही है कि इन कत्लेआम में शामिल दोषियों को सजा मिल सके। आज इन कत्लेआम के १५ वर्ष बाद एक और कमीशन बैठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इन कत्लेआम में शामिल लोग जोकि हजारों बेगुनाहों के लिए दोषी हैं, आजाद घूम रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि इस आयोग का शीघ्र गठन हो और उसे एक निश्चित समय में रिपोर्ट देने को कहा जाए ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिल सके।